

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3294
23 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात क्लस्टर

3294. श्री पी.सी. मोहन:

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सहायक, डाउनस्ट्रीम और मूल्य वर्धित इस्पात इकाइयों की चुनौतियों का समाधान करने और उनकी विकास क्षमता का दोहन करने के प्रयास में इस्पात समूहों के लिए एक रूपरेखा नीति का मसौदा तैयार किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने ऐसी नीति के लिए कोई निधि आवंटित की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार भारत में स्टील ग्रेड कोयले की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए किस तरीके से विचार कर रही है;
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा वर्ष 2014 से 2022 तक विदेशी ठेकेदारों से स्टील ग्रेड कोयले की खरीदे के लिए खर्च की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या आंध्र प्रदेश राज्य को कोई नया स्टील क्लस्टर स्वीकृत किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (छ) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सहायक और डाउनस्ट्रीम क्लस्टर या मूल्य वर्धित क्लस्टर के अंतर्गत आता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क) और (ख): जी हाँ। स्टील क्लस्टरों के लिए एक रूपरेखा नीति तैयार की गई है। इस उद्देश्य हेतु वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में एक लाख रुपये की टोकन राशि आवंटित की गई है।

(ग) और (घ): कोकिंग कोयले की समग्र मांग स्वदेशी उत्पादन से पूरी नहीं होती है क्योंकि देश में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले/कोकिंग कोयले (निम्न-राख-कोयला) की आपूर्ति सीमित है। तदनुसार, भारतीय इस्पात उद्योग मुख्यतया आयातित कोकिंग कोयले पर निर्भर रहा है। देश में स्वदेशी रूप से उत्पादित अधिकांश कोकिंग कोयले में राख की मात्रा अधिक है जो इसे इस्पात निर्माण के लिए अनुपयोगी बनाती है जिसके कारण वर्ष 2019-20 में 51.83 एमटी तथा 2020-21 में 51.20 एमटी कोकिंग कोयले का आयात किया गया था। देश में इस्पात ग्रेड कोयले की उपलब्धता को बढ़ाने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) कोकिंग कोयले के उत्पादन को मौजूदा 45 एमटी से बढ़ाकर वर्ष 2029-30 तक 140 एमटी करने के लिए कोकिंग कोयला मिशन की शुरुआत की गई है।

(2) इस्पात मंत्री, भारत सरकार तथा ऊर्जा मंत्री, रूसी फेडरेशन के मध्य इस्पात निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कोकिंग कोयले के संबंध में दिनांक 14.10.2021 को एक समझौता जापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू से कोकिंग कोयले के स्रोतों के विविधीकरण द्वारा भारतीय इस्पात उद्योग को लाभ प्राप्त होगा जिससे भारत में उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोयले की आपूर्ति की दीर्घावधि वचनबद्धता के कारण इस्पात निर्माताओं के लिए इनपुट लागत में कमी हो सकेगी।

(ड) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा वर्ष 2014 से 2022 के दौरान विदेशी ठेकेदारों से इस्पात ग्रेड कोयले (पीसीआई सहित) की खरीद के लिए व्यय की गई राशि का वर्षवार ब्योरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (फरवरी 2022 तक)
व्यय (करोड़ रुपये में)	12745	10448	13871	20543	23704	21551	16059	27476

(च) और (छ): जी नहीं। आंध्रप्रदेश राज्य के लिए किसी नए स्टील क्लस्टर को अनुमोदन नहीं दिया गया है।
